आज़ादी का अमृत महोत्सव

जागृति

वर्ष : 66 अंक : 4 मुंबई मार्च 2022

केंद्रीय मंत्री श्री नारायण राणे ने कोंकण क्षेत्र में उद्यमिता और व्यापार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित एमएसएमई कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया

एमएसएमई मंत्री ने कुडाल में कोनबैक-स्फूर्ति बांस क्लस्टर का उद्घाटन किया

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका

खादी और ग्रामोद्योग आयोग

कामये दुःखतप्तानाम्।
प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्॥

वर्ष: 66 अंक: 4 मुंबई मार्च 2022

जागृति

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका

सम्पादकीय मण्डल

अध्यक्ष

श्रीमती प्रीता वर्मा

संपादक

एम. राजन बाबू

सह संपादक

संजीव पोसवाल

उप संपादक

सुबोध कुमार

डिजाईन व पृष्ठसज्जा

संजय सोमदे
वरिष्ठ कलाकार

चंद्रशेखर पुनवटकर
कलाकार

दिलिप पालकर
कलाकार

प्रचार, फ़िल्म एवं लोक शिक्षण
कार्यक्रम निदेशालय द्वारा
खादी और ग्रामोद्योग आयोग,
ग्रामोदय, 3 इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम),
मुंबई - 400056 के लिए ई-प्रकाशित
ईमेल: kvicpub@gmail.com
वेबसाइट: www.kvic.org.in

आवश्यक नहीं कि पत्रिका में प्रकाशित लेखों तथा विचारों से खादी और ग्रामोद्योग आयोग अथवा संपादक सहमत हों

इस अंक में.....

समाचार सार 03-19

- केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कोंकण क्षेत्र में उद्यमिता और व्यापार के अवसर बढ़ाने के मकसद से आयोजित एमएसएमई कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया 3
- केवीआईसी ने बांस उद्योग की उच्च लाभप्रदता के लिए बांस चारकोल पर "निर्यात पर रोक " हटाने का प्रस्ताव रखा.....7
- केवीआईसी के "चरखा क्रांति" ने गांधीवादी मान्यताओं पर माहौल बनाया, राष्ट्रपति के अभिभाषण में है इसका जिक्र.....9
- माननीय केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी और केवीआईसी के अध्यक्ष, श्री विनय कुमार सक्सेना ने राजघाट में केवीआईसी के बहु उद्देश्यीय प्रशिक्षण केंद्र का दौरा 14
- खादी के रोजगार अभियान ने सुंदरबन में बाघ- पीड़ित बाली द्वीप का कायाकल्प कर दिया 15
- लोकसभा में सवाल का जवाब देते हुए माननीय मंत्री, एमएसएमई ने खादी प्राकृतिक पेंट के बारे में जानकारी दी.....17
- मुंबई में डीएन सिंह रोड स्थित खादी एम्पोरियम पर केवीआईसी द्वारा नकली खादी उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध लगाया.....18
- पीएमईजीपी- आत्मनिर्भरता का एक उपकरण.....19

प्रेस कवरेज व सोशल मीडिया 20-23

सिंधुदुर्ग में 200 करोड़ रुपये की लागत से एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित होगा

केंद्रीय मंत्री श्री नारायण राणे ने कोंकण क्षेत्र में उद्यमिता और व्यापार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित एमएसएमई कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया

कुडाल में कोनबैक-स्फूर्ति बांस क्लस्टर का उद्घाटन करते हुए श्री नारायण राणे ने कहा,

सिर्फ़ आम और काजू ही नहीं, बांस भी आय का एक बड़ा स्रोत

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री श्री नारायण राणे ने 25 फरवरी 2022 को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में 200 करोड़ रुपये के खर्च से एमएसएमई-प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की घोषणा की। एमएसएमई - प्रौद्योगिकी केंद्र उद्योग, विशेष रूप से एमएसएमई, को उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और क्षेत्र के नियोजित और बेरोजगार युवाओं को उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल सेवाएं प्रदान करने के लिए सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी, ईक्यूबेशन के साथ-साथ परामर्श सहायता प्रदान करेगा।

श्री राणे ने यह घोषणा एमएसएमई मंत्रालय द्वारा सिंधुदुर्ग में आयोजित दो दिवसीय एमएसएमई कॉन्क्लेव (25 और 26 फरवरी) के उद्घाटन के मौके पर की। कॉन्क्लेव का उद्देश्य कोंकण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए प्रौद्योगिकी, उत्पाद विकास और कौशल के उपयोग में उद्यमिता और व्यापार के अवसरों को बढ़ावा देना है।

कॉन्क्लेव के महत्व पर प्रकाश डालते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, "ऐसे कॉन्क्लेव उद्यमियों, नीति निर्माताओं और अन्य प्रमुख हितधारकों के लिए सूचनाओं के आदान- प्रदान, नवोन्मेषी विचारों और पारस्परिक व्यापार के अवसरों की तलाश करने के लिए एक खुले संवाद में शामिल होने के लिए

एक महत्वपूर्ण मंच का काम करते हैं।'

श्री राणे ने कहा, "इस सम्मेलन का मकसद सिंधुदुर्ग इलाके को औद्योगिक क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर लाना है।" उन्होंने बताया कि कैसे सिंधुदुर्ग के अधिकांश निवासियों को नौकरी के अवसरों की तलाश में जीविकोपार्जन के लिए शहर छोड़ना पड़ा। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें वर्तमान परिदृश्य में बदलाव लाना होगा जहां सिंधुदुर्ग में आय पैदा हो और जहां हमारी आने वाली पीढ़ी इससे लाभान्वित हो सके।

एमएसएमई मंत्रालय ने कोंकण में करीब 2000 से अधिक नई विनिर्माण इकाइयां स्थापित की हैं, महाराष्ट्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं

मंत्री ने कोंकण क्षेत्र में एमएसएमई मंत्रालय की पहलों की सराहना की और कहा कि महाराष्ट्र में विशेष रूप से कोंकण क्षेत्र में रोजगार सृजन की काफी संभावनाएं हैं। मंत्री ने कहा कि सरकार पीएमईजीपी (प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम), स्फूर्ति (पारंपरिक उद्योगों के पुनर्जनन के लिए कोष की योजना), हनी मिशन और कुम्हारों के सशक्तीकरण के लिए कुम्हार सशक्तीकरण योजना जैसे प्रमुख कार्यक्रमों के सही कार्यान्वयन द्वारा क्षेत्र में उद्यमिता और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

श्री राणे ने कहा कि मंत्रालय ने 2016 के बाद से कोंकण क्षेत्र में लगभग 2,000+ नई विनिर्माण इकाइयां स्थापित करके उद्यमिता को व्यापक प्रोत्साहन दिया है, जिसके परिणामस्वरूप 16,400 प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन हुआ है। इन परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए मंत्रालय ने 71.65 करोड़ रुपये की सब्सिडी राशि का वितरण किया है।

मंत्री ने रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले और आसपास के क्षेत्रों के ग्रामीण कारीगरों को बिजली के कुम्हारी पहिये,

मधुमक्खी के बक्से और अगरबत्ती बनाने की मशीनें भी वितरित कीं। उन्होंने 25 खादी कारीगरों को भी सम्मानित किया और प्रशिक्षण पूर्ण होने के प्रमाण पत्र सौंपे। इसके अलावा, 10 पीएमईजीपी लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे गए जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) की स्वरोजगार गतिविधियों से जुड़कर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढाएंगे।

कॉन्क्लेव के दौरान मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं की प्रस्तुति भी मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दी गई, जिसमें ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के उद्यमियों और युवाओं ने हिस्सा लिया।

अतिरिक्त सचिव और विकास आयुक्त, एमएसएमई, श्री शैलेश कुमार सिंह ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए उद्यम पंजीकरण और चैंपियंस पोर्टल जैसी विभिन्न योजनाओं के महत्व और प्रासंगिकता पर जोर दिया, जिनका कोविड-19 महामारी के दौरान सकारात्मक प्रभाव पड़ा।

एमएसएमई मंत्री द्वारा कुडाल में कोनबैक-स्फूर्ति बांस क्लस्टर का उद्घाटन

इससे पहले दिन में, एमएसएमई मंत्री ने कुडाल में कोनबैक-स्फूर्ति (कोंकण बांस और गन्ना विकास केंद्र - पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए फंड की योजना) बांस क्लस्टर का उद्घाटन किया। क्लस्टर 300 कारीगरों को मदद करेगा। एमएसएमई मंत्रालय ने क्लस्टर की स्थापना के लिए 1.45 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।

कोंकण क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए उपलब्ध अवसरों पर प्रकाश डालते हुए श्री राणे ने कहा, "न सिर्फ आम और काजू बल्कि बांस को भी आय का स्रोत माना जाना

चाहिए।" उन्होंने कहा कि लोगों को बांस के कारोबार की ओर आकर्षित करने के लिए कोनबैक-स्पूर्ति क्लस्टर का आयोजन किया गया है और स्थानीय लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए।

सचिव एमएसएमई, बी.बी. स्वैन, अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, विनय कुमार सक्सेना, अध्यक्ष-कॉयर बोर्ड, डी. कुप्पुरामू और कोनबैक के निदेशक मोहन होडावड़ेकर इस अवसर पर उपस्थित थे।

कोनबैक के संबंध में

कोनबैक एक स्वतंत्र गैर-लाभकारी संगठन है जो एक आत्मनिर्भर संस्थागत पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में विकसित हुआ है और इसके पास भारतीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए प्रीमियम बांस उत्पादों के डिजाइन, प्रोटोटाइप और उत्पादन के लिए पूर्ण विकसित सुविधा है। इसके पास गरीब बांस उत्पादकों को बड़े आकर्षक बाजारों से जोड़ने की व्यवस्था उपलब्ध है और यह पहले से ही एक मॉडल के रूप में उभरा है जिसका भारत समेत विदेशों अन्य जगहों पर अनुकरण किया जा रहा है।

पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए फंड की योजना (स्फूर्ति):

क्लस्टर विकास को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई मंत्रालय की एक पहल है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) खादी के लिए क्लस्टर विकास को बढ़ावा देने के लिए नोडल एजेंसी है। यह योजना पारंपरिक उद्योगों और कारीगरों को प्रतिस्पर्धी बनाने और उनकी दीर्घकालिक संधारणीयता में सहायता प्रदान करने के लिए समूहों में संगठित करती है। इसका उद्देश्य पारंपरिक उद्योग कारीगरों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए निरंतर रोजगार प्रदान करना है।

केवीआईसी ने बांस उद्योग की उच्च लाभप्रदता के लिए बांस चारकोल पर "निर्यात पर रोक" हटाने का प्रस्ताव रखा

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने सरकार से बांस उद्योग में कच्चे बांस के इष्टतम उपयोग और उच्च लाभप्रदता के लिए बांस चारकोल पर "निर्यात पर रोक" हटाने का अनुरोध किया है। भारतीय बांस उद्योग के सामने आज सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बांस के अपर्याप्त उपयोग के कारण अत्यधिक उच्च इनपुट लागत है।

हालांकि, बांस चारकोल का निर्यात बांस अपशिष्ट का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करेगा और इस तरह बांस के व्यवसाय को अधिक लाभदायक बना देगा।

केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, श्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर बांस उद्योग के वृहद लाभ के लिए बांस चारकोल पर निर्यात प्रतिबंध हटाने की मांग की है।

भारत में, बांस का उपयोग अधिकांशतः अगरबत्ती के निर्माण में किया जाता है, जिसमें अधिकतम 16 प्रतिशत, अर्थात बांस की ऊपरी परतों का उपयोग बांस की छड़ियों के निर्माण के लिए किया जाता है, जबकि शेष 84 प्रतिशत बांस पूरी तरह से बेकार हो जाता है। अगरबत्ती और बांस शिल्प उद्योगों में उत्पन्न बांस अपशिष्ट का व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप, गोल बांस की छड़ियों के लिए बांस इनपुट लागत 25,000 रुपये से 40,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन के बीच है, जबकि बांस की औसत लागत 4,000 रुपये से 5,000

रुपये प्रति मीट्रिक टन के बीच में है। इसकी तुलना में, चीन में बांस की कीमत 8,000 रुपये से 10,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन है, लेकिन 100 प्रतिशत अपशिष्ट उपयोग के कारण उनकी इनपुट लागत 12,000 रुपये से 15,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन है।

केवीआईसी के अध्यक्ष श्री सक्सेना ने कहा कि "बांस का कोयला" बनाकर बांस के अपशिष्ट का सबसे अच्छा उपयोग किया जा सकता है, यद्यपि घरेलू बाजार में इसका बहुत सीमित उपयोग है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी अत्यधिक मांग है। बहरहाल, भारतीय बांस उद्योग अपनी "निर्यात मनाही" के कारण इस अवसर का लाभ नहीं उठा पा रहा है। उद्योग के बार-बार के अनुरोधों पर विचार करते हुए केवीआईसी ने सरकार से बांस चारकोल पर निर्यात प्रतिबंध हटाने पर विचार करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि यह न केवल उद्योग को विशाल वैश्विक मांग का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा, बल्कि बांस के अपशिष्ट के समुचित उपयोग से वर्तमान केवीआईसी इकाइयों की लाभप्रदता को भी बढ़ाएगा और इस तरह प्रधानमंत्री के "अपशिष्ट से संपदा" के विजन में योगदान देगा।

उल्लेखनीय है कि बांस चारकोल की विश्व आयात मांग 1.5 से 2 बिलियन अमरीकी डालर के दायरे में है और हाल के वर्षों में 6 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बारबेक्यू के लिए बांस का कोयला लगभग 21,000 रुपये से 25,000 रुपये प्रति टन के हिसाब से बिकता है। इसके अतिरिक्त, इसका उपयोग मिट्टी के पोषण के लिए और सक्रिय चारकोल के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में भी किया जाता है। अमेरिका, जापान, कोरिया, बेल्जियम, जर्मनी, इटली, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों में आयात की बढ़ती मांग नगण्य आयात शुल्क पर रही है।

यह उल्लेख करना उचित है कि एचएस कोड 141100 के तहत बांस उत्पादों के लिए निर्यात नीति में एक संशोधन 2017 में किया गया था, जिसमें सभी बांस उत्पादों के निर्यात को ओजीएल श्रेणी में रखा गया था और ये निर्यात के लिए "मुक्त" थे। हालांकि, बैम्बू चारकोल, बैम्बू पल्प और अनप्रोसेस्ड शूट्स के निर्यात को अभी भी प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है।

इससे पूर्व, बांस आधारित उद्योगों, विशेष रूप से अगरबत्ती उद्योग में अधिक रोजगार सृजित करने के लिए, केवीआईसी ने 2019 में, कच्ची अगरबत्ती के आयात और वियतनाम तथा चीन से भारी मात्रा में आयात किए जाने वाले गोल बांस की छड़ियों पर आयात शुल्क में नीतिगत बदलाव के लिए सरकार से अनुरोध किया था। इसके बाद सितंबर 2019 में वाणिज्य मंत्रालय ने कच्ची अगरबत्ती के आयात पर "प्रतिबंध" लगा दिया और जून 2020 में वित्त मंत्रालय ने गोल बांस की छड़ियों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया।

नीतिगत परिवर्तनों के निहितार्थ के रूप में, भारत में अगरबत्ती और बांस-शिल्प उद्योगों की सैकड़ों बंद इकाइयों का पुनरुद्धार किया गया है। नीतिगत बदलाव के बाद, केवीआईसी ने अपने अग्रणी कार्यक्रम प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम (पीएमईजीपी) के तहत 1658 नई अगरबत्ती विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित की हैं। इसी प्रकार, देश भर में 1121 नई बांस शिल्प संबंधी इकाइयां भी स्थापित की गई हैं। इसने न केवल बांस के उपयोग को इष्टतम बनाया है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी रोजगार का भी सृजन किया है।

केवीआईसी के "चरखा क्रांति" ने गांधीवादी मान्यताओं पर माहौल बनाया, राष्ट्रपति के अभिभाषण में है इसका जिक्र

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2022: पिछले 7 वर्षों में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा शुरू की गई "चरखा क्रांति" का परिणाम है कि खादी में जबरदस्त रूप से (घातांकीय) वृद्धि हुई है। राष्ट्रपति ने बजट सत्र से पहले संसद में अपने संबोधन में इसका उल्लेख किया। केवीआईसी ने भारत और विदेशों में गांधीवादी विचारों और चरखे के प्रतीकवाद के प्रचार के लिए कई महत्वपूर्ण चरखे बनाए, जिसने खादी को और अधिक लोकप्रिय बनाया तथा बड़े पैमाने पर विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 31 जनवरी को संसद में राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में और एक दिन पहले अहमदाबाद के साबरमती रिवरफ्रंट में महात्मा गांधी के 74वें शहीद दिवस पर 100 वर्ग मीटर की दीवार भित्ति का अनावरण करते हुए गृह मंत्री श्री अमित शाह ने खादी की सफलता को स्वीकार किया।

दिलचस्प बात यह है कि केवीआईसी की स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी, लेकिन अगले 58 वर्षों यानी 2014 तक इसने खादी, चरखा या महात्मा गांधी से जुड़े किसी अन्य प्रतीक को लोकप्रिय बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। "खादी" और "गांधी" का इस्तेमाल केवल राजनीतिक लाभ के लिए किया जाता था। वर्ष 2014 के बाद नरेन्द्र मोदी की सरकार ने खादी को लोकप्रिय बनाने व महात्मा गांधी के विचारों और चरखे के प्रतीकवाद को दुनिया भर में फैलाने के लिए ठोस प्रयास किए। महात्मा गांधी की जयंती हो या शहादत, केवीआईसी ने गांधीवादी विचारों को फैलाने के लिए अनोखे कार्यक्रम आयोजित किए।

पिछले 7 वर्षों के दौरान केवीआईसी ने दुनिया के सबसे बड़े लकड़ी व स्टील के चरखे, कलाई की घड़ियों पर दुनिया का सबसे छोटा चरखा, मिट्टी के कुल्हड़ों से बना गांधी जी का विश्व का सबसे बड़ा दीवार भित्ति चित्र, खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज, धरोहर चरखा संग्रहालय और कई अन्य स्मारक बनाए। चरखा जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई में गांधी जी का हथियार था, 2017 में पहली बार किसी बाहरी देश में पहुंचा। तब से बापू का चरखा दुनिया के 60 देशों में पहुंच चुका है।

केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से ही खादी और चरखे को न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाने के लिए ठोस कदम उठाए गए। इसने खादी के उत्पादन और बिक्री को बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाई और इस तरह बापू के ग्रामोदय के सपने को साकार करने में योगदान दिया। चरखा क्रांति ने देश भर में खादी कारीगरों को रिकॉर्ड 55,000 उन्नत चरखे का वितरण भी किया, जिससे उन्हें स्वरोजगार प्रदान किया गया।

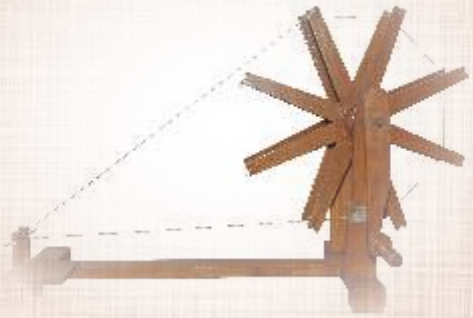

*1956 से 2014 कोई महत्वपूर्ण गतिविधि/कार्यक्रम नहीं हुए

5 जुलाई, 2016 नई दिल्ली में इन्दिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष और संसद सदस्य श्री अमित शाह ने विश्व का सबसे बड़ा लकड़ी का चरखा स्थापित किया था।

18 अक्टूबर, 2016- माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लुधियाना में स्वतंत्र भारत में अब तक का सबसे बड़ा चरखा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

21 मई, 2017- तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष और संसद सदस्य श्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेनलेस स्टील चरखा स्थापित किया गया।

21 मई, 2017- तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष और संसद सदस्य श्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में धरोहर चरखा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया।

2 अक्टूबर, 2017- युगांडा में पहली बार विदेश की धरती पर लकड़ी के एक बड़े चरखे का अनावरण किया गया।

15 अप्रैल, 2018- चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में बिहार के मोतिहारी में पूर्व कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह द्वारा स्टेनलेस स्टील चरखे का अनावरण किया गया।

7 जून, 2018- दक्षिण अफ्रीका का पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन खादीमय दिखा और ट्रेनों को खादी के कपड़े में लपेटा गया। यह रेलवे स्टेशन वह जगह है जहां 125 साल पहले 1893 में गांधी जी को प्रथम श्रेणी, "केवल गोरे" डिब्बे में अपनी सीट छोड़ने से इनकार करने पर ट्रेन से उतार दिया गया था। केवीआईसी द्वारा विदेश की धरती पर इस तरह का यह पहला कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

26 जून, 2018-अहमदाबाद के साबरमती रिवरफ्रंट में ग्रैंड स्टेनलेस स्टील चरखा स्थापित किया गया। तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष और सांसद श्री अमित शाह ने चरखे का अनावरण किया था।

31 जनवरी, 2019 - भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में एनडीएमसी भवन में महात्मा गांधी की टेराकोटा कुल्हड़ से बनी दुनिया की सबसे बड़ी दीवार भित्ति का अनावरण किया था।

30 जनवरी, 2020----दुनिया का सबसे छोटा चरखा अद्वितीय खादी कलाई घड़ियों में इस्तेमाल किया गया, इसे तत्कालीन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के मंत्री श्री नितिन गडकरी ने लॉन्च किया था।

4 फरवरी, 2022 को केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने पिछले 7 वर्षों में खादी की सफलता के विशेष उल्लेख के लिए माननीय राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया। माननीय प्रधान मंत्री की प्रेरणा से, केवीआईसी द्वारा शुरू की गई "चरखा क्रांति" ने भारत और दुनिया भर में खादी, चरखा और गांधीवादी मूल्यों को लोकप्रिय बनाया है।

2017 और 2018 में खादी प्रदर्शनियों के दौरान 60 देशों में चरखे को भेजा गया था !

2 अक्टूबर, 2021- लद्दाख के उपराज्यपाल श्री आर. के. माथुर द्वारा लेह में खादी के कपड़ों से बना 1400 किलोग्राम वजनी विश्व के सबसे बड़े अति महान राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया गया।

30 जनवरी, 2022- अहमदाबाद में साबरमती रिवरफ्रंट पर स्थापित मिट्टी के कुल्हड़ों से बने महात्मा गांधी की भव्य दीवार भित्ति चित्र। यह भारत का दूसरा और गुजरात का पहला दीवार भित्ति चित्र है, जिसका अनावरण माननीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने किया था।

2014-15 से 2020-21 तक - खादी का उत्पादन बढ़ाने के लिए देश भर में खादी कारीगरों को 55,000 नए मॉडल के चरखे और 9,000 आधुनिक करघे वितरित किए गए।

18 फरवरी, 2022 को माननीय केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी और केवीआईसी के अध्यक्ष, श्री विनय कुमार सक्सेना ने राजघाट में केवीआईसी के बहु उद्देश्यीय प्रशिक्षण केंद्र का दौरा किया। माननीय मंत्री ने स्वरोजगार के माध्यम से ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने और ग्रामोद्योगों को मजबूत करने के केवीआईसी के प्रयासों की सराहना की।

खादी के रोजगार अभियान ने सुंदरबन में बाघ-पीड़ित बाली द्वीप का कायाकल्प कर दिया

09 फरवरी, 2022: सुंदरबन के घने मैंग्रोव इलाकों में निस्तेज बाघ-पीड़ित बाली द्वीप का ऐतिहासिक कायाकल्प हुआ है। यह द्वीप जो आजादी के बाद से ही विकास की मुख्यधारा से पूरी तरह से कट गया था, अब खादी गतिविधियों से गतिमान हो गया है।

बाली द्वीप में सौ से अधिक बाघ विधवाएं (स्थानीय भाषा में इन्हें बाग बिधोबा कहा जाता है) है। ये 2018 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) की कताई गतिविधि से जुड़ी थीं।

ये अब आधुनिक सुविधाओं और चरखा, करघे जैसे आधुनिक उपकरणों और विपणन सहायता पर गर्व कर सकती हैं। इन महिला कारीगरों को ये सुविधाएं स्थायी आजीविका प्रदान करने के लिए उपलब्ध कराई गई हैं।

इस द्वीप में खादी गतिविधियों को शुरू करने के लिए केवीआईसी ने तीन साल पहले एक अस्थायी ढांचा स्थापित किया था, जिसे अब स्थायी वर्कशेड में परिवर्तित कर दिया गया है।

केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने बाली द्वीप में खादी कारीगरों के लिए नवनिर्मित 3000 वर्ग फुट के वर्क शेड और 500 वर्ग फुट के सामान्य सुविधा केन्द्र का उद्घाटन किया है।

''टाइगर विक्टिम खादी कटाई केन्द्र'' अब 125 नए मॉडल के चरखों, 15 आधुनिक करघों से सुसज्जित है, जो बाली द्वीप की लगभग 150 महिला कारीगरों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं।

केवीआईसी ने इन कारीगरों को 'यार्न डाइंग मशीन' और रेडीमेड गारमेंट तैयार करने की मशीनें भी प्रदान की हैं। इस केन्द्र का 95 लाख रुपये की लागत से आधुनिकीकरण किया गया है, जिसका वित्तपोषण केवीआईसी ने अपनी खादी सुधार और विकास कार्यक्रम (केआरडीपी) और खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड योजना के तहत किया है। यह केन्द्र पश्चिम बंगाल के एक स्थानीय खादी संस्थान द्वारा चलाया जा रहा है।

श्री सक्सेना ने कहा कि बाली द्वीप पर खादी गतिविधियां प्रधानमंत्री के समाज के वंचित वर्गों को सशक्त

बनाने और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के विजन से प्रेरित हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि बाली द्वीप में खादी गतिविधियों से बाघ विधवाओं की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित होगी, क्योंकि बाघों के हमलों में इनके परिवारों के कमाने वाले व्यक्तियों की मृत्यु के बाद इनका भविष्य अंधकारमय हो गया था। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार गतिविधियों से इन असहाय महिला कारीगरों के पुनर्वास में मदद मिलेगी, इसके साथ-साथ यह अन्य परिवारों को भी सम्मानजनक आजीविका अर्जित करने के लिए कताई और बुनाई गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

खादी गतिविधियों को अपनाकर ये कारीगर प्रतिदिन 200 रुपये तक कमाने में समर्थ होंगे। उन्होंने कहा कि यह विचार इन परिवारों को मछली पकड़ने के लिए गहरे पानी में उतरने या घने मैंग्रोव में जाने से रोकने और बाघों के हमलों के खतरे को कम करने में भी मदद करेगा।

यह उल्लेखनीय है कि केवीआईसी ने वर्ष 2018 में बाली द्वीप में कताई केन्द्र का उद्घाटन किया था और कताई गतिविधि के लिए स्थानीय महिला कारीगरों को 75 चरखे वितरित किए थे। केवीआईसी ने द्वीप में स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए इस द्वीप के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सशक्त बनाने के लिए जीवित मधुमक्खी कॉलोनी वाले 500 मधुमक्खी-बक्से भी वितरित किए थे।

इन कारीगरों को केवीआईसी द्वारा व्यापक प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया था।

लोकसभा में सवाल का जवाब देते हुए माननीय एमएसएमई मंत्री ने खादी प्राकृतिक पेंट के बारे में जानकारी दी

एमएसएमई मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) की एक इकाई, कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट (केएनएचपीआई), जयपुर द्वारा गाय के गोबर से खादी प्राकृतिक पेंट विकसित किया गया है। खादी प्राकृतिक पेंट पर्यावरण के अनुकूल और लागत प्रभावी है। केएनएचपीआई द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट का परीक्षण नेशनल टेस्ट हाउस, गाजियाबाद (भारत सरकार), नेशनल टेस्ट हाउस, मुंबई (भारत सरकार) और श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च, दिल्ली (एक आईएसओ प्रमाणित परीक्षण प्रयोगशाला) में किया गया है और इसने पेंट के लिए आवश्यक मापदंडों को पूरा किया।

यह परिकल्पना की गई है कि खादी प्राकृतिक पेंट के निर्माण से स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा, स्थायी रोजगार पैदा होगा और किसानों और गौशालाओं के लिए अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार भी पैदा होगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और देश में ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों तक पलायन को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।

गाय का गोबर, प्राकृतिक पेंट के निर्माण में उपयोग किया जाने वाला एक प्रमुख घटक है। 100 किग्रा. 500 लीटर पेंट बनाने में गाय के गोबर का उपयोग किया जाता है। इसलिए, पेंट इकाइयों की स्थापना से गाय के गोबर के उपयोग में मदद मिलेगी और इससे पर्यावरण को साफ करने में मदद मिलेगी।

केएनएचपीआई खादी प्राकृतिक पेंट के निर्माण में प्रशिक्षण प्रदान करता है। एमएसएमई मंत्रालय की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) योजना के तहत प्राकृतिक पेंट निर्माण इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। खादी प्राकृतिक पेंट के निर्माण की तकनीक देश के गांवों में कई इकाइयों को प्रदान की गई है।

यह जानकारी केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे ने 3 फरवरी 2022 को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

केवीआईसी ने मुंबई में डी.एन. रोड स्थित खादी एम्पोरियम पर नकली खादी उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध लगाया

5 फरवरी, 2022: खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), जिसने हाल के वर्षों में, नकली / गैर-खादी उत्पादों की बिक्री के खिलाफ "शून्य सहिष्णुता" को अपनाया है, ने अपने सबसे पुराने खादी संस्थान- मुंबई खादी और ग्रामोद्योग एसोसिएशन (एमकेवीआईए), का "खादी प्रमाणन" रद्द कर दिया है, जो 1954 से मुंबई में डा.डी.एन. रोड स्थित एक हैरिटेज बिल्डिंग , मेट्रोपॉलिटन इंश्योरेंस हाउस में प्रतिष्ठित "खादी एम्पोरियम" चला रहा था।

केवीआईसी ने पाया कि डॉ डीएन रोड पर उक्त खादी एम्पोरियम असली खादी की आड़ में गैर-खादी उत्पाद बेच रहा था। नियमित निरीक्षण के दौरान, केवीआईसी के अधिकारियों ने एम्पोरियम से नमूने एकत्र किए जो गैर-खादी उत्पाद पाए गए। केवीआईसी ने, आयोग द्वारा जारी "खादी प्रमाणपत्र" और "खादी चिह्न प्रमाणपत्र" के मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए मुंबई खादी और ग्रामोद्योग एसोसिएशन को कानूनी नोटिस जारी किया। पंजीकरण रद्द करने के साथ, अब खादी एम्पोरियम एक वास्तविक खादी आउटलेट नहीं है और अब उसे एम्पोरियम से खादी उत्पादों को बेचने की अनुमति भी नहीं है। केवीआईसी ब्रांड खादी की विश्वसनीयता और लोकप्रियता का दुरूपयोग करके आपराधिक विश्वासघात और जनता को धोखा देने के लिए एमकेवीआईए के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर भी विचार कर रहा है।

केवीआईसी ने वर्ष 1954 में, खादी एम्पोरियम का संचालन और प्रबंधन एमकेवीआईए, एक पंजीकृत खादी संस्थान को इस कड़ी शर्त पर सौंप दिया था कि वह एम्पोरियम से केवल "वास्तविक खादी उत्पाद" ही बेचेगा। हालांकि, हाल के वर्षों में ऐसा प्रचारित किया जा रहा था कि यह एम्पोरियम केवीआईसी द्वारा चलाया जा रहा था और एमकेवीआईए ने नकली खादी उत्पादों को बेचकर अनुचित व्यापार प्रथाओं में लिप्तता जारी रखी और इस तरह लोगों को धोखा दिया।

यह उल्लेख करना उचित है कि केवीआईसी ने पिछले कुछ वर्षों में अपने ब्रांड नाम "खादी इंडिया" के दुरुपयोग और अपने ट्रेडमार्क में उल्लंघन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। अब तक केवीआईसी ने खुदरा ब्रांड फैबइंडिया सहित 1200 से अधिक व्यक्तियों और फर्मों को "खादी" ब्रांड नाम का दुरुपयोग करने और "खादी" के नाम से गैर-खादी उत्पादों को बेचने के लिए कानूनी नोटिस जारी किए हैं। केवीआईसी ने फैबइंडिया से 500 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है जो मुंबई उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। पिछले साल, केवीआईसी ने ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स - Amazon, Flipkart और Snapdeal - को 140 वेब लिंक को हटाने के लिए मजबूर किया, जो गैर-खादी उत्पादों को "खादी" के रूप में बेच रहे थे।

ऐसे कई मामलों में, केवीआईसी ने उल्लंघनकर्ताओं को अदालतों में घसीटा और उन्हें "खादी" ब्रांड नाम का दुरुपयोग करने से रोकने के आदेश प्राप्त किए। नतीजतन, कई उल्लंघनकर्ताओं ने माफी मांगी और भविष्य में ब्रांड नाम "खादी" का उपयोग नहीं करने का वचन दिया। ●●

पीएमईजीपी- आत्मनिर्भरता का एक उपकरण

'बीप्रीनूर'- विकास क्षीरसागर

पीएमईजीपी श्रृंखला और स्फूर्ति श्रृंखला की सफलता की कहानियों की अपार सफलता के बाद, इस बार हम आपके लिए केवीआईसी के बेहद लोकप्रिय 'हनी मिशन' कार्यक्रम की सफलता की कहानियां लेकर आए हैं।

इस सप्ताह की शुरुआत 'बीप्रीनूर' विकास क्षीरसागर की सफलता की कहानी है, जिन्हें लंबे समय से मधुमक्खी पालन का शौक है। उनके जुनून का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि, उन्होंने अपनी कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ दी ताकि वे पूरे समय मधुमक्खी पालन कर सकें! केवीआईसी से 15 दिनों का पूरा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद, उन्हें 'एपिस मेलिफेरा' के 10 बक्से मिले, जिसे उन्होंने अब 62 बक्से में गुणा किया है! यह दिखाता है कि विकास क्षीरसागर ने सफलता की राह पर किस तरह का समर्पण, ईमानदारी और कड़ी मेहनत की थी।

वर्तमान में, विकास के पास 160 से अधिक बक्से हैं और वह अब अपने गांव में 100 लोगों को रोजगार प्रदान करता है! वह 'जीवो जीवस्य जीवनं' के दर्शन में दृढ़ता से विश्वास करते हैं, जिसका अर्थ है कि इस पृथ्वी पर प्रत्येक जीवित प्राणी अन्य जीवों पर निर्भर है जो वास्तव में 'हनी मिशन' के दर्शन के लिए वसीयतनामा है।

हनी मिशन कार्यक्रम के सफलता की कहानी

दृढ़ संकल्प, कौशल और रचनात्मकता के साथ तमिलनाडु में महिलाएं Beekeeping के लिए आगे आई हैं। महिलाएं पुरुष प्रधान उद्योग की बेड़ियां तोड़ते हुए एक नई राह की ओर आगे बढ़ रही हैं।

तमिलनाडु में कुल 325 लाभार्थियों में से 147 लाभार्थी महिलाएं हैं जो कुल लाभार्थियों के 45 प्रतिशत के बराबर है। मधुमक्खी पालन गतिविधियां इन Queen Beekeepers के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ साथ देश भर में महिला उद्यमिता के लिए एक उदाहरण भी स्थापित कर रही हैं। तमिलनाडु में SFURTI योजना के तहत एक शहद प्रसंस्करण प्लांट, विनोवा सेवा संगम की स्थापना की गई थी। यह प्लांट पूरी तरह से महिलाओं द्वारा चलाया जाता है व महिलाओ को आत्मनिर्भर बनाने में पूर्णतः समर्थन करता है।

प्रेस कवरेज

rissadiary.com

HOME TOP STORIES NATIONAL SPORTS BUSINESS DISTRICTS CITY NRO COLUMNS

Rs 200 crore MSME Technology Centre to be set up in Sindhudurg

New Delhi : Union Minister for Micro, Small & Medium Enterprises (MSME), Narayan Rane today announced the establishment of **MSME-Technology Centre** with an outlay of Rs. 200 Crore, in

Ads

Working on all metals

Latest news

PM Gati Shakti-National Master Plan for Steel Sector

Bill Book Free Download for PC - MY Bill Book App

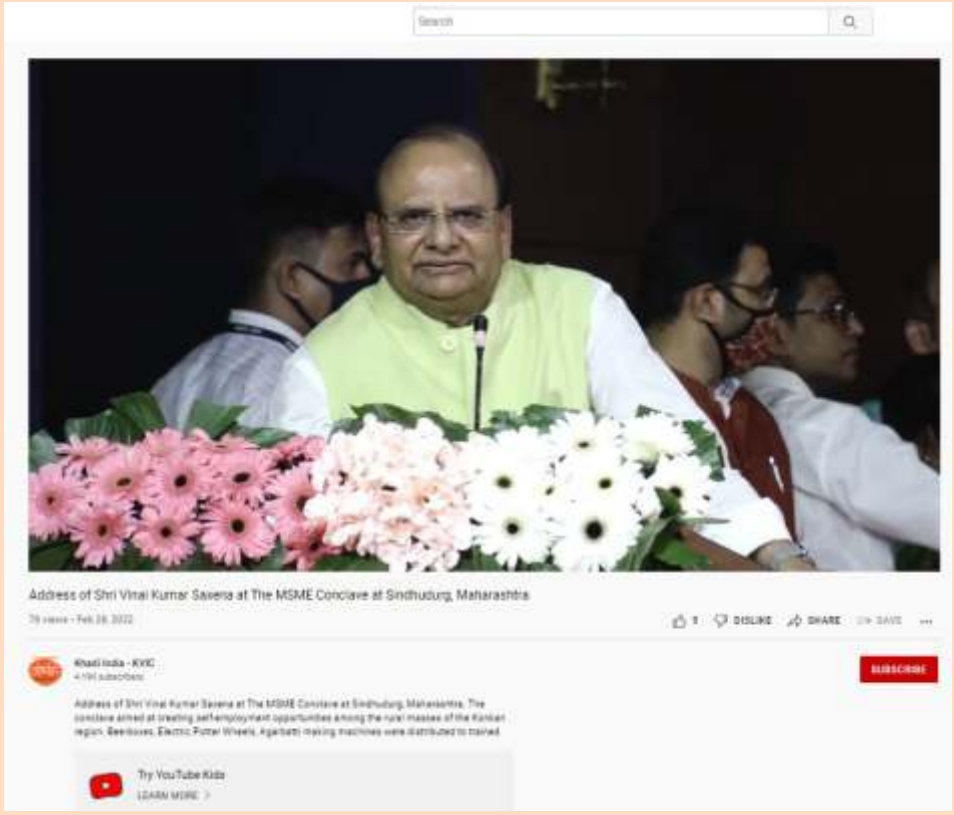

Address of Shri Vinai Kumar Saxena at The MSME Conclave at Sindhudurg, Maharashtra

Khadi India - KVIC

SUBSCRIBE

Try YouTube Kids

प्रेस कवरेज

MSME Technology Centre with an outlay of Rs 200 Cr to be set up in Sindhudurg to boost employment creation

Micro, Small & Medium Enterprises (MSMEs) and startups have changed the face of the Indian economy in the past few years. It has created millions of jobs on the ground and has helped Micro, Small and Medium businesses to grow in the nation with contact support from Government, who have helped them with Technology, capital and talent.

Taking the vision forward, Union Minister for Micro, Small & Medium Enterprises, Narayan Rane announced the establishment of MSME-Technology Centre with an outlay of Rs. 200 Crore in Sindhudurg. The announcement was made on 25 Feb during the inauguration of a two-day MSME Conclave (25 and 26 February) in Sindhudurg, Maharashtra. The MSME Conclave aimed at promoting entrepreneurship and trade opportunities in Konkan Region.

Speaking about the significance of the conclave, Union Minister Narayan Rane said, "such conclaves serve as an important platform for entrepreneurs, policymakers and other key stakeholders to engage in an open dialogue to exchange information, innovative ideas and exp

MSME-Technol

AffairsCloud

HOME EXAMS CURRENT AFFAIRS MONT

नारायण राणे ने सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र में MSME कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया; यूनियन बैंक MSME RuPay क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया

AffairsCloud YouTube Channel - Click Here

AffairsCloud APP Click Here

KNN Knowledge & News Network

Home Economy MSME Sectors State Knowledge Resource Global Features

You are here: Home > MSME

25/02/2022 04:07pm

MSME Minister unveils Rs 200 cr MSME Technology Centre at Sindhudurg

MSME Minister unveils Rs 200 cr MSME Technology Centre at Sindhudurg

Mumbai, Feb 25 (KNN) Union MSME Minister Narayan Rane announced the formation of MSME Technology Centre worth Rs 200 crore at Sindhudurg in Maharashtra on Friday during the inaugural session of two-day MSME Conclave in the presence of senior government officials.

One the first day, MSME Minister Rane said, "The Ministry is presently focussing to create a benchmark for MSMEs across the country by scaling them to new heights in terms of exports, quality of products, contribution to GDP and providing World class infrastructure to all MSMEs in India."

Minister Rane also inaugurated the Konbac Sfurti Cluster at Kudal which will support 300 artisans and 500 honey bee boxes,100 electric pottery wheels and 100 agarbatti

Own a Piece of Best Startups

आज़ादी का अमृत महोत्सव

केवीआईसी सोशल मीडिया में -फेसबुक पर

SPECIAL DAYS

केवीआईसी सोशल मीडिया में - इंस्टाग्राम पर

स्पेशल डे पोस्ट

आज़ादी का
अमृत महोत्सव

पर्यावरणानुकुल उत्पादों का एक स्थान

बहुमुखी एवं मनमोहक
खादी डिजाइनर परिधानों
जैसे पर्यावरणानुकूल उत्पादों का एक स्थान
खादी वस्त्र, हर्बल उत्पाद,
रसायन रहित अगरबत्तियां,
विषाणु रहित एवं एन्टी फंगल शहद,
नैसर्गिक एवं आयुर्वेदिक सौन्दर्य उत्पाद
जैसे साबुन एवं शैम्पू,
हाथ कागज एवं पारंपरिक हस्तशिल्प
तथा अन्य उत्पादों की विशाल श्रृंखला

KVIC

खादी और ग्रामोद्योग आयोग
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार
ग्रामोदय, 3, इर्ला रोड़, विले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई-400 056.
वेबसाईट : www.kvic.org.in

Khadi India

"भारत में हम रोजगार सृजन करते है तथा समृध्दि बुनतें हैं"